RNA: Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE, और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण





सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दी / SC allows sale of green fireworks in Delhi

संदर्भ:

दीपावली से पहले, 15 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में पटाखों पर लगी पूरी रोक में छूट दी। अदालत ने 18 से 20 अक्टूबर तक "ग्रीन" पटाखों की बिक्री की अनुमति दी, जिन्हें नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) द्वारा प्रमाणित किया गया है।

ग्रीन क्रैकर्स: पर्यावरण के अनुकूल पटाखे

ग्रीन क्रैकर्स ऐसे पर्यावरण के अनुकूल पटाखे हैं जिन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) ने विकसित किया है। इन्हें हानिकारक उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया गया है।

मख्य विशेषताएँ:

- **कम प्रदूषण:** पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30-4<mark>0% कम प्रदूषक</mark> उत्सर्जित होते हैं।
- पर्यावरण-मित्र डिजाइन: छोटे गोले, कम कच्चे माल का उपयोग, और धूल-नियंत्रक (dust-suppressant) तत्वों का समावेश।
- अल्प अवशेष: राख और धूल का उत्सर्जन कम होने से धुएँ में कमी आती है।
- सतत विकल्पः भले ही कोई भी पटाखा पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता, ग्रीन क्रैकर्स त्योहारों के दौरान एक सुरक्षित और स्वच्छ विकल्प प्रदान करते हैं।

यह पहल परंपरा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है।

CSIR-NEERI द्वारा विकसित ग्रीन क्रैकर्स के प्रकार

2018 में **CSIR-NEERI** ने तीन मुख्य प्रकार के ग्रीन क्रैकर्स विकसित किए:

- SWAS (Safe Water Releaser): जल उत्सर्जन को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करता है।
- STAR (Safe Thermite Cracker): थर्माइट-आधारित पटाखों को सुरक्षित बनाता है।
- SAFAL (Safe Minimal Aluminium): न्यूनतम एल्युमिनियम का उपयोग कर धूल और गैस उत्सर्जन घटाता है।

इन संस्करणों में **पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर** को हटा दिया गया है, जिससे उत्सर्जन कम होता है, लेकिन त्योहारी चमक और ध्वनि सुरक्षित सीमा के भीतर बनी रहती है।

आदेश के प्रभाव:

- **ग्रीन पटाखों के लिए टेस्ट केस**: यह निर्णय दीवाली के दौरान ग्रीन पटाखों का वायु गुणवत्ता पर वास्तविक प्रभाव जांचने के लिए एक परीक्षण के रूप में काम करेगा।
- **नियामक चुनौतियाँ:** लाइसेंसधारियों, NEERI पंजीकरण और PESO लाइसेंसिंग के नियमों को लागू करना महत्वपूर्ण होगा।
- भविष्य में संभावित ढील: यदि यह "टेस्ट केस" सफल रहता है, तो भविष्य में प्रतिबंध में और ढील पर विचार किया जा सकता है।
- संतुलन बनाए रखनाः आदेश पर्यावरणीय सुरक्षा और सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों के बीच संतूलन बनाए रखने की चुनौती को उजागर करता है।

GREEN CRACK

THE SCIENCE OF CLEANER FIREWORKS FOR DIWALI



ग्रीन क्रैकर्स से जुड़े चिंताएँ और जोखिम

- कम उत्सर्जन गैसें: CSIR-NEERI के अनुसार, ग्रीन क्रैकर्स पारंपरिक पटाखों की तुलना में नाइट्स **ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड** का उत्सर्जन कम करते हैं।
- उच्च सूक्ष्म कण: हालांकि, २०२२ में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि ग्रीन क्रैकर्स अब भी अत्यंत सुक्ष्म कणों (ultra-fine particles) का उच्च स्तर छोडते हैं।
- स्वास्थ्य जोखिम: ये सुक्ष्म कण PM2.5 और PM10 से भी अधिक हानिकारक माने जाते हैं. जिससे श्वसन तंत्र और अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।













भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा / India-Middle East-Europe Economic Corridor

संदर्भ:

भारत-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) अब सुर्खियों में है, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और रेड सी में व्यवधानों ने इसकी भविष्य की व्यवहार्यता और रणनीतिक क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में कॉरिडोर के सफल संचालन के लिए अनुकूलन और लचीली रणनीतियों की आवश्यकता है।



भू-राजनीतिक चुनौतियाँ और बदलते परिदृश्य:

- हामास-इज़राइल संघर्ष: ७ अक्टूबर २०२३ के बाद से जारी हामास-इज़राइल संघर्ष ने पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ा दी है। इसने IMEC (India-Middle East-Europe Corridor) की व्यवहार्यता पर असर डाला और संघर्ष समाधान में बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता को उजागर किया।
- अब्राहम समझौते का प्रभाव: 2020 में हुए अब्राहम समझौते ने इज़राइल-अरब संबंधों में सुधार लाया था, लेकिन नई हिंसक घटनाओं के चलते इसका सकारात्मक प्रभाव कम हो गया है, जिससे वैश्विक व्यवस्था पर दबाव पड़ा है।
- रेड सी में हूथी हमले: रेड सी में हूथी हमलों के कारण वैश्विक व्यापार मार्ग बाधित हुए हैं। जहाजों को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया जा रहा है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं और आर्थिक नुकसान हो रहा है।
- IMEC मार्गों में अनुकूलन: भारत और अरब देशों को क्षेत्रीय शक्ति समीकरण और सुरक्षा चिंताओं के अनुसार IMEC मार्गों को अनुकूलित करना होगा, जिससे रणनीतिक योजना में आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित की जा सके।
- विशेषज्ञों की सलाह: क्षेत्रीय अस्थिरता के बावजूद IMEC की बहु-सदस्य संरचना का उपयोग करके लचीले साझेदारी मॉडल और निरंतर सहयोग बनाए रखना चाहिए, जो क्षेत्र के लिए नए आर्थिक सौदे की संभावना बढ़ा सकता है।

इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC): एक परिचय

- परियोजना का उद्देश्य: IMEC एक बहुराष्ट्रीय कनेक्टिविटी पहल है, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को शिपिंग, रेलवे और सड़क मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है।
- संबंधित पहलः यह परियोजना पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) का हिस्सा है, जो 67 द्वारा संचालित है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में टिकाऊ बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित है।
- घोषणा और सदस्यता: IMEC की घोषणा सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। समझौते में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के रणनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- मुख्य मार्गः
 - ईस्टर्न कॉरिडोर: भारत और अरब की खाड़ी को समुद्री मार्ग से जोड़ता है।
 - नॉर्दर्न कॉरिडोर: अरब की खाड़ी से यूरोप तक रेल और समुद्री मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसमें कई मध्य पूर्वी देशों के माध्यम से रेलवे नेटवर्क, हाइफा पोर्ट और यूरोप तक समुद्री मार्ग शामिल हैं।
- ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी: परियोजना में
 अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल और क्लीन एनर्जी
 पाइपलाइन के माध्यम से ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी योजनाएं भी शामिल हैं।
- संभावित लाभ:
 - ट्रांजिट समय और लागत में कमी।
 - सप्लाई चेन का विविधीकरण, विशेषकर सुएज नहर के विकल्प के रूप में।
 - आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान।
 - स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा।











RNA DAILY CURRENT AFFAIRS 17

17 अक्टूबर 2025



भारत ने DRDO's के स्वदेशी लड़ाकू पैराशूट का सफल परीक्षण किया / India successfully tests DRDO's indigenous combat parachute

संदर्भ:

DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक सैन्य कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को 32,000 फीट की ऊँचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के सफल होने से देशी पैराशूट सिस्टम के बल में शामिल होने के रास्ते खुले हैं।

मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS): प्रमुख विशेषताएँ-

- उच्च-ऊँचाई क्षमताः MCPS भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल होने वाला एकमात्र पैराशूट सिस्टम है जिसे 25,000 फीट से ऊपर तैनात किया जा सकता है। हाल ही के परीक्षण में, IAF टीम ने 32,000 फीट से छलांग लगाई और पैराशूट 30,000 फीट पर खोला।
- टैक्टिकल उन्नयन: सिस्टम में उन्नत युद्धक सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे कि धीमी उतराई की दर और बेहतर नेविगेशन/स्टियरिंग क्षमता। यह पैरादूपर्स को उच्च ऊँचाई से सुरक्षित निकलने, सटीक नेविगेशन और लक्षित क्षेत्र में सुरक्षित उतराई करने में सक्षम बनाता है।
- NaviC एकीकरणः MCPS भारत के स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम (NaviC) के साथ संगत है। इससे संचालन में स्वायत्तता सुनिश्चित होती है और संभावित विदेशी हस्तक्षेप या डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) के दौरान सुरक्षा मिलती है।
- कम रखरखाव: आयातित उपकरणों की तुलना में, यह स्वदेशी सिस्टम रखरखाव और मरम्मत में कम समय लेता है, जिससे उपकरण की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित होती है और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटती है।

रणनीतिक महत्तः

- आत्मिनिर्भरता को बढ़ावा: MCPS का विकास DRDO के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADRDE), आगरा और डिफेंस बायोइंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी (DEBEL), बेंगलुरु द्वारा किया गया है। यह परियोजना "आत्मिनिर्भर भारत" पहल के उद्देश्य के अनुरुप है।
- **हवाई अभियान क्षमता में सुधार:** सफल परीक्षण विशेष बलों के संचालन और उच्च-ऊँचाई युद्ध क्षमताओं को मजबूत करता है, विशेषकर भारत की सीमाओं के पास कठन डलाकों में।
- औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का परिचय

 स्थापना और उद्देश्यः DRDO, 1958 में स्थापित, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य देश को रक्षा प्रौद्योगिकी और सिस्टम में आत्मनिर्भर बनाना है।

मुख्य मिशन और गतिविधियाँ:

- डिज़ाइन और विकास: भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत सेंसर, हथियार प्रणाली और सहायक उपकरण विकसित करता है।
- समाधान प्रदान करनाः युद्धक दक्षता को बढ़ाने और सैनिकों की भलाई सुधारने के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करता है।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना।
- सामाजिक योगदानः DRDO के अनुसंधान से नागरिक जीवन में उपयोगी "स्पिनऑफ" लाभ भी मिलते हैं।

विशेषज्ञता के क्षेत्र:

- ० एयरोनॉटिक्स, आयुध और हथियार प्रणाली
- युद्ध वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन
- इंजीनियरिंग सिस्टम
- मिसाइल, नौसेना प्रणाली
- उन्नत कम्प्यूटिंग और सिमुलेशन
- विशेष सामग्री
- ० जीवन विज्ञान

मुख्य तथ्य:

- संगठनः लगभग ४१ प्रयोगशालाओं और ५ DRDO यंग साइंटिस्ट लैब्स का नेटवर्क।
- मुख्यालयः नई दिल्ली, भारत।
- विभागीय अधीनताः रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत।











RNA DAILY CURRENT AFFAIRS

17 अक्टूबर 2025



भारत २०३० शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए तैयार / India set to host २०३० centenary Commonwealth Games

संदर्भ:

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 **सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स** के लिए अहमदाबाद, भारत को प्रस्तावित मेज़बान शहर के रूप में सुझाया है। अंतिम निर्णय 26 नवंबर 2025 को ग्लारगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जनरल असेंबली में लिया जाएगा। भारत ने पिछली बार 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी।

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स:

- **मेजबान शहर:** भारत के अहमदाबाद को २०३० कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है।
- प्रतिस्पर्धी बोली: नाइजीरिया की राजधानी अबुजा भी इस आयोजन की मेजबानी के लिए प्रतिस्पर्धा में थी।
- भारत का अनुभवः भारत ने इससे पहले २०१० में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का सफल आयोजन किया था।
- **सेंवुरी संस्करण:** २०३० संस्करण कॉमनवेल्थ गेम्स क<mark>ा शताब</mark>्दी संस्करण होगा, जिसकी शुरुआत १९३० में हैमिल्टन, कनाडा में हुई थी।
- **भारत के लिए महत्त्व:** इस आयोजन को भारत के 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की महत्वाकांक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Here's a table comparing India's two hosting opportunities:

Year	Host City	Outcome/Context	Significance for India
2010	Delhi	Games were marred by delays, poor planning, and corruption allegations.	First time India hosted the Games.
2030	Ahmedabad	Recommendation subject to final approval in November.	Seen as a stepping stone towards hosting the 2036 Olympics.

कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६: ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजन:

• मेजबान शहरः ग्लासगो, स्कॉटलैंड

• तिथियाँ: २३ जुलाई - २ अगस्त २०२६

• खेलों की संख्या: 10

प्रतिभागी राष्ट्रः ७४ कॉमनवेल्थ राष्ट्र और क्षेत्र

• मुख्य विवरण:

- ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ने बढ़ती लागत के कारण मेजबानी वापस ले ली, जिसके बाद नए मेजबान की तलाश शुरू हुई।
- ग्लासगो ने पहले 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी।
- o 2026 गेम्स को कम खर्चीला और सीमित कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा।
- o खेलों की संख्या बर्मिंघम २०२२ (१९ खेल) से घटाकर १० खेल कर दी गई है।

- प्रमुख खेल जो शामिल नहीं होंगे: बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलॉन और तीरंदाजी।
- पैरास्पोर्ट्स को अहमियत दी जाएगी, जिसमें 6 खेलों में 47 फाइनल होंगे।

भविष्य का संकेत: 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद, भारत को मेजबान शहर के रूप में सिफारिश की गई है।

कॉमनवेल्थ गेम्सः परिचय और इतिहास

परिचयः कॉमनवेल्थ गेम्स एक चार वर्षीय अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है, जिसमें कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के एथलीट हिस्सा लेते हैं। इसे अक्सर "फ्रेंडली गेम्स" कहा जाता है। इस आयोजन में पारंपरिक खेलों के साथ-साथ पैरास्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है।

इतिहास और विकास:

- शुरुआतः कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रस्ताव १८९१ में आया और पहली बार इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में १९३० में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किया गया।
- ्र नाम में बदलाव:
 - ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स: 1954-1966
 - ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्सः १९७०-१९७४
 - कॉमनवेल्थ गेम्सः १९७८-वर्तमान
- समान अवसर और समावेशिताः 2002 से, विकलांग एथलीटों को उनके राष्ट्रीय टीमों में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और उनके लिए समर्पित पैरास्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया गया।

प्रतिभागी और प्रदर्शन:

- टीमों की संख्या: 74 डेलीगेशन हिस्सा लेते हैं, जबिक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स के केवल 56 सदस्य देश हैं। यह इसलिए क्योंकि यूके के कुछ ओवरसीज़ टेरिटरीज, क्राउन डिपेंडेंसीज और द्वीप राज्य, जैसे एंगुइला और फॉकलैंड आइलैंड्स, अलग-अलग टीमों के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- नियमित प्रतिभागी: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ने हर कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया है।











17 अक्टूबर 2025



बाघ की हरित स्थिति का आकलन / Tiger's Green Status Assessment

संदर्भ:

आईयूसीएन की पहली ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार, एशिया में बाघों की संख्या "गंभीर रूप से घट गई" है। हालांकि, संरक्षण प्रयास उनके स्वदेशी आवासों में आबादी की बहाली की उम्मीद जगाते हैं।

 रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि बाघों को उनके सभी उपयुक्त और ऐतिहासिक आवासों में पुनर्स्थापित किया जाए, तो जंगली क्षेत्रों में उनकी संख्या 25,000 से अधिक हो सकती है, जो वर्तमान वैश्विक आबादी (लगभग 5,500) से पांच गुना अधिक है।

टाइगर के लिए ग्रीन स्टेटस असेसमेंट: संरक्षण और भविष्य

परिचय: IUCN का ग्रीन स्टेटस असेसमेंट किसी प्रजाति की रिकवरी को मापता है। यह मूल्यांकन करता है कि प्रजाति पूरी तरह से स्वस्थ है, जीवित रहने योग्य है और पारिस्थितिक कार्य कर रही है। यह IUCN रेड लिस्ट का पूरक है।

० प्रारंभ: २०१२

ग्रीन स्टेट्स के स्तर: किसी प्रजाति की आबादी और संरक्षण सफलता को आठ स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है:

- 1. वाइल्ड में विलुप्त (Extinct in the Wild)
- 2. गंभीर रूप से क्षीण (Critically Depleted)
- 3. काफी हद तक क्षीण (Largely Depleted)
- 4. मध्यम रूप से क्षीण (Moderately Depleted)
- 5. हल्के रूप से क्षीण (Slightly Depleted)
- 6. पूरी तरह से स्वस्थ (Fully Recovered)
- 7. गैर-क्षीण (Non-Depleted)
- 8. अनिर्णीत (Indeterminate)

मुख्य निष्कर्षः

- मानव गतिविधियों के कारण बाघों की आबादी में भारी गिरावट और निवास क्षेत्र में कमी हुई है।
- कई आबादी क्षेत्रीय रूप से विलुप्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।
- मौजूदा संरक्षण प्रयासों ने और अधिक गिरावट को रोका, छह क्षेत्रों में विलुप्त होने से बचाया और कुछ आबादी की रिकवरी में मदद की।
- यदि ये प्रयास न होते, तो बाघों का Species Recovery Score केवल
 ५% होता और वे गंभीर रूप से संकटग्रस्त होते।

भविष्य की संभावनाएँ:

- सतत और सशक्त संरक्षण के साथ, बाघ लंबी अविध में महत्वपूर्ण रिकवरी कर सकते हैं।
- अगले 100 वर्षों में वे सभी निवास क्षेत्रों में फिर से लौट सकते हैं।

लीप्स 2025 / LEAPS 2025

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई पहल **LEAPS 2025** का उद्घाटन किया, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम **गति शक्ति** की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया।

LEAPS 2025: लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस, एडवांसमेंट और परफॉर्मेंस शील्ड: LEAPS 2025 भारत की लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता को मापने और वैश्विक सप्लाई चेन में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख पहल है। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गति शक्ति के उद्देश्यों के अनुरुप है।

शुरुआत और प्रबंधन:

- लॉन्चः उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत
- उद्देश्यः भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में बेहतरीन प्रथाओं,
 नवाचार और नेतृत्व को मान्यता देना और पुरस्कार प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **लक्ष्यः** दक्षता, पारदर्शिता और लचीलापन बढ़ाना, सरकार, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- कवरः हवाई, सड़क, समुद्री और रेलवे माल परिवहन, वेयरहाउसिंग, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट, MSMEs, स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थान।
- ्र **श्रेणियाँ:** १३ श्रेणियों में आवेदन, ५ प्रमुख सेगमेंट में विभाजित:
 - 1. **कोर लॉजिस्टिक्स:** एयर, रोड, रेल, मरीन, मल्टीमॉडल और वेयरहाउस सेवा प्रदाता
 - 2 **MSME:** लॉजिस्टिकम सेवा प्रदाता
 - 3. **स्टार्टअप्स:** लॉजिस्टिक्स तकनीक और ऑपरेशन प्रदाता
 - 4. **संस्थान:** लॉजिस्टिक्स को बढावा देने वाले शैक्षिक संस्थान
 - विशेष श्रेणियाँ: ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) सेवा प्रदाता

सस्टेनेबिलिटी पर जोर: पहल ग्रीन लॉजिस्टिक्स, ESG प्रथाओं और नवाचार पर ध्यान देती है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकासशील भारत 2047 के विज्ञन के अनुरूप हैं।

महत्तः: LEAPS 2025 पीएम गति शक्ति और NLP 2022 के ढांचे पर आधारित है, जो भारत में भविष्य-तैयार, टिकाऊ लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को विकसित करता है और मेक इन इंडिया व राष्ट्रीय आर्थिक विकास को मजबूत करता है।













1500x4 26000/- 7 1 1

- 🥯 रोज़ाना लाइव क्लासेस
- सांप्ताहिक ट्रेस्ट्र
- 🛮 क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में) 🗟
- लाइव डाउट सेशन
- रोजाना प्रैक्टिस प्रश्न





FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET LEARN HOW TO TRADE

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH

COMBO OFFERS

E4000/-

OFFER PRICE

₹2800/-



एक निवेश समझदारी से..









FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

Invest in Knowledge Grow Your Wealth

Course fee

₹1999/-



एक निवेश समझदारी से..

PURTFULIU BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

- (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
- > Long-Term Investing Foundations
- » Principles of Value Investing and Stock
- » Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- » Active Portfolio Management Techniques
- » Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

TYEAR







